मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3491

10.08.2026 को उत्तर के लिए

अवक्रमित वन भूमि की बहाली

3491. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे :
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके :
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न राज्यों में ग्रीन इंडियन मिशन के अंतर्गत बहाल की गई अवक्रमित वन भूमि के कुल क्षेत्र का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नगर वन (शहरी वन) के तेजी से विकास से राज्य के प्रमुख शहरों में हरित आवरण और वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2026-27 के दौरान इन वृक्षारोपण के लिए संवितरित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) नए लगाए गए पौधों के रख-रखाव में स्थानीय समुदायों और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में वृक्षारोपण क्षेत्रों की जीवित रहने की दर का सटीक पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग और ड्रोन निगरानी को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में, ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत नौ मिशनों में से एक हरित भारत मिशन (जीआईएम) को वर्ष 2015-16 से एकीकृत भूदृश्य दृष्टिकोण के माध्यम से अवक्रमित वन एवं गैर-वन भूदृश्यों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से अब तक हरित भारत मिशन के अंतर्गत 17 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में 1,84,467 हेक्टेयर क्षेत्र को पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार के अंतर्गत लाया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। मंत्रालय शहरी हरित आवरण तथा पारिस्थितिकीय लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से 2026-27 की अवधि में 600 नगर वन तथा 400 नगर वाटिकाओं के विकास हेतु नगर वन योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। परिकल्पना की गई है कि नगर वन हरित आवरण में उल्लेखनीय योगदान देंगे तथा ऐसे पारिस्थितिकीय परिसंपत्तियों का सृजन करेंगे जिनमें वायु गुणवत्ता एवं सूक्ष्म जलवायु में सुधार की क्षमता होगी। हरित भारत मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक स्वीकृत कार्यकलापों के लिए छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों को 57.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नगर वन योजना के अंतर्गत पौधरोपण एवं उससे संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्यों के स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय प्राधिकरण 'काम्पा' द्वारा धनराशि जारी की जाती है।

(घ) हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण एवं उसके रखरखाव संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुसार स्थानीय संस्थाओं, जिनमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ (जेएफएमसी), ग्राम वन समितियाँ (वीएफसी) तथा अन्य सामुदायिक आधारित संगठन शामिल हैं, के माध्यम से किया जाता है। स्वीकृत कार्यकलापों में जहाँ भी प्रावधान किया गया है, वहाँ स्थानीय समुदायों, जिनमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि शामिल हैं, को विशेष रूप से पौधरोपण के रखरखाव, पौधशालाओं की स्थापना तथा संबंधित आजीविका कार्यकलापों में भी शामिल किया जाता है।

(ङ) हरित भारत मिशन के अंतर्गत पौधरोपण की निगरानी केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण के अनुसार की जाती है। मिशन प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिनमें पौधरोपण स्थलों का भू-टैगिंग, जीआईएस आधारित मानचित्रण, भू-टैग युक्त छायाचित्र तथा केएमएल फाइलें शामिल हैं। राज्य वन विभाग समय-समय पर क्षेत्रीय निरीक्षण तथा तृतीय-पक्ष के माध्यम से निगरानी करते हैं तथा उत्तरजीविता के आकलन के आधार पर गैप फिलिंग एवं रखरखाव जैसे सुधारात्मक उपायों को अपनाते हैं। जहाँ राज्यों द्वारा ड्रोन आधारित निगरानी की जाती है, वहाँ यह क्षेत्रीय सत्यापन और अधिक सुदृढ़ हो सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है, भू-सत्यापन द्वारा समर्थित सुदूर-संवेदन तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक दो वर्ष में वन आवरण का आकलन करता है तथा इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित करता है।

*****

अनुलग्नक-I

'अवक्रमित वन भूमि की बहाली' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके तथा डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2015-16 से ग्रीन इंडिया मिशन की गतिविधियों के माध्यम से बहाली के अंतर्गत लाया गया राज्य-वार कुल क्षेत्रफल:

क्र.सं.	**राज्य**	**वृक्षारोपण/पारिस्थितिकीय बहाली का सृजन (भौतिक, हेक्टेयर में)**
1	आंध्र प्रदेश	1,433
2	अरुणाचल प्रदेश	5,314
3	छत्तीसगढ़	22,601
4	हरियाणा	3,755
5	हिमाचल प्रदेश	1,299
6	जम्मू और कश्मीर	1,778
7	कर्नाटक	2,722
8	केरल	14,290
9	मध्य प्रदेश	32,831
10	महाराष्ट्र	5,223
11	मणिपुर	17,488
12	मिजोरम	19,643
13	ओडिशा	20,711
14	पंजाब	7,168
15	सिक्किम	6,567
16	उत्तराखंड	14,836
17	पश्चिम बंगाल	2,606
18	उत्तर प्रदेश	4,202
कुल		**184467**

*****